







**मराठा आरक्षण : 31 जनवरी तक सर्वेक्षण...**



**मुंबई :** मराठा आरक्षण पर उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र सरकार की उपचारात्मक याचिका के समर्थन में राज्यभर में सवा लाख से अधिक गणनाकारों एवं अधिकारियों की मदद से अनिवार्य सर्वेक्षण शुरू होगा। राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विष्णु पाटिल ने कहा कि गणनाकारों के इस प्रक्रिया को त्रुटिहीन रखने का निर्देश दिया गया है। यह प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। उन्होंने एक बयान में कहा कि अधीक्षकों और अधिकारियों समेत सवा लाख से अधिक गणनाकारों को यह कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है। उनका प्रशिक्षण पूरा हो गया है। राज्य के सभी 36 जिलों, 27 नगर निगमों और सात छावनी बोर्ड में सर्वेक्षण मंगलवार को शुरू होगा जो 31 जनवरी तक चलेगा। पाटिल ने कहा कि राजस्व विभाग महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए यह काम कर रहा है।

**धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में 3 गिरफ्तार**



तहत मामला दर्ज किया गया। इस बीच, भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में मुफीज अहमद नाम के 55 वर्षीय व्यक्ति को एक सोसायटी के गेट से भगवान राम की तस्वीर वाला झांडा हटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

**मुंबई :** शहर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के कम से कम चार मामले दर्ज होने के बाद मुंबई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, पुलिस ने मंगलवार को कहा। सभी चार घटनाएं 22 जनवरी को दर्ज की गईं, उसी दिन जब अयोध्या के राम मंदिर में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हआयोजित किया गया था। पहली घटना में, मुंबई के वकोला इलाके में पिंपलेश्वर मंदिर में प्रार्थना के दैरान भगवान राम के झंडे का अपमान करने के आरोप में 27 वर्षीय सऊद कुरेशी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 295, 504 और 506 के तहत मामला दर्ज किया है। गोवंडी पुलिस द्वारा संभाले गए दूसरे मामले में, 23 वर्षीय पृथ्वीराज जोगड़ को गिरफ्तार किया गया, जो महाराष्ट्र के लातूर का निवासी है। उन्होंने कथित तौर पर अपने मोबाइल पर भड़काऊ स्टेट्स पोस्ट किया, जिसके परिणामस्वरूप आईपीसी की धारा 153 (ए) और 295 (ए) के

**क्या मुंबई की सड़कें बंद कर देनी चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC को लगाई फटकार... बीएमसी अधिकारियों से 15 फरवरी तक मांग जवाब।**



**मुंबई :** बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई की सड़कों को बंद किए जाने को लेकर अहम टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्या मुंबई की सड़कों को बंद किया जाना चाहिए क्योंकि नगर निगम कर्मचारी मराठा आरक्षण के सर्वेक्षण कार्य और चुनाव ड्यूटी में व्यस्त हैं।

**मौतों के संबंध दायर की गई थी याचिका**

मुंबई में गड्ढों से हुई मौतों के संबंध में एक याचिका दायर की गई थी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र उपचाय और जज आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने बहु-मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को फटकार लगाई। उन्होंने मामले में हलफनामा दाखिल करने के लिए बीएमसी को याचिका के जवाब में हलफनामा

दाखिल करने का निर्देश दिया था। मंगलवार को बीएमसी की ओर से पेश वकील ने हलफनामा दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है। हाईकोर्ट ने बीएमसी को 15 फरवरी तक अपना हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ ने कहा कि हलफनामे में यह भी बताया जाना चाहिए कि बीएमसी शहर में काम पूरा करने के लिए किस तारीख को योजना बना रही है।

**मुंबई में उपद्रवियों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मीरा रोड में हुआ था बवाल**

**त्रैक मरम्मत कार्य के दौरान लोकल से टक्कर में तीन रेलवे कर्मचारियों की मौत हो गई**

**मुंबई:** पश्चिमी रेलवे (डब्ल्यूआर) के तीन कर्मचारियों की पालघर जिले के वसई के पास एक लोकल ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जब वे सिग्नलिंग की समस्या ठीक कर रहे थे, पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को बताया। सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना सोमवार रात 8.55 बजे वसई रोड और नायांवं स्टेशनों के बीच हुई जब लोकल चर्चिट की ओर जा रही थी। मृतकों की पहचान मुख्य सिग्नलिंग इंप्रेक्टर (भायंदर) वासु मित्रा, इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग मेटेनर (वसई रोड) सोमानाथ उत्तम लाम्बुत्रे और हेल्पर सचिन वानखड़े के रूप में की गई। उन्होंने कहा कि ये सभी

कर्मचारी पश्चिम रेलवे के मुंबई डिवीजन के सिग्नलिंग विभाग से थे।

अधिकारी ने कहा, वे कुछ सिग्नलिंग बिंदु को ठीक करने गए थे जो सोमवार शाम को खारब हो गया था। अधिकारियों ने कहा कि पश्चिम रेलवे ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारियों ने तीनों मृतकों के परिवार के सदस्यों को तत्काल राहत के तौर पर 55,000 रुपये का भुगतान किया है।

**‘यह मुंबई है, यूपी नहीं’... वायरल वीडियो में लोगों को भड़काने वाला शख्स गिरफ्तार**



**मुंबई:** दो समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद मुंबई से स्टेटी मीरा रोड इलाके में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोगों को भड़काने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अबू शेहमा शेख को उनके फेसबुक पोस्ट के संबंध में नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 153 ए, 505 (2) और आईटी अधिनियम की धारा 66 सी के तहत गिरफ्तार किया गया था। अपने वायरल वीडियो में शेख को यह कहते हुए सुना गया, “यह यूपी नहीं है, यह मुंबई है।” इसके बाद वह सांप्रदायिक टिप्पणी करने लगता है जिससे वह मुसीबत में पड़ गया है।

स्थानीय पुलिस, मुंबई पुलिस, पालघर पुलिस, ठाणे ग्रामीण पुलिस, आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स), एमएसएफ (महाराष्ट्र सुरक्षा बल) और एसआरपीएफ को इलाके में तैनात किया गया है। डीसीपी जयंत बजबले ने कहा, “मुंबई से स्टेटी हिंसा कर रही है।” 21 जनवरी की रात मीरा रोड पर दो समुदायों के बीच झड़प हो गई। मीरा भयंदर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्रीकांत पाठक ने सभी से क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की।

“हम घटना की जांच कर रहे हैं। आरोपियों के खिलाफ ही कार्रवाई की जाएगी। मैं सभी से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस ने समय पर कार्रवाई की है। हम सीसीटीवी फुटेज देखकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। छोटे-मोटे शरारती तत्व अभी भी हैं।” उपद्रव पैदा करने की कोशिश करें, “उन्होंने कहा नियानगर में हिंसा को लेकर 13 लोगों

को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच, महाराष्ट्र के

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के निर्देश पर तेरह लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य सदियों की पहचान की जा रही है, उपमुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कहा, “मीरा के नयानगर इलाके में हुई घटना की पूरी जानकारी भयंदर को कल रात ही ले जाया गया था। सोमवार सुबह 3.30 बजे तक मैं मीरा-भयंदर पुलिस कमिशनर से लगातार संपर्क में था। पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को हिंसा करने में लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की प्रक्रिया चल रही है। महाराष्ट्र में कानून-व्यवस्था को बाधित करने कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को बद्रिश नहीं किया जाएगा।” पुलिस उपायुक्त जयंत बजबले के मुताबिक, “रविवार रात कीरब 11 बजे दोनों समुदायों के बीच संघर्ष तब शुरू हुआ, जब हिंदू समुदाय के कुछ लोग मीरा रोड से स्टेटी नाम के गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि ये सभी से क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की।

**बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेश मंत्रालय को दिया निर्देश**

**मुंबई:** बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को दिवाने के डॉक्टरों के पास एक पैनल ने कहा कि उनकी चिकित्सा विधियों का अनुसार किया जा सकता है, जिसके बाद न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति फिरदेश पूरीवाला की पीठ ने यह निर्देश पारित किया। पीठ ने कहा, “हमारे पास संयुक्त अरब अमीरात के डॉक्टरों को लेकर 13 लोगों

में भारतीय उच्चायुक्त से प्रमाणित करने और (व्यक्ति) की स्वास्थ्य स्थिति की पुष्टि करने का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जैसा कि एस दहनाह अस्पताल में उसका इलाज कर रहे स्थानीय सरकारी डॉक्टरों के परामर्श से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए डॉक्टरों का एक पैनल बनाने और एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था।



कानून के मुताबिक केस डायरी मेंटेन नहीं रखने पर बॉम्बे हाई कोट ने पुलिस को लगाई फटकार

## डीजीपी को दिए निर्देश...



**मुंबई :** बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में कानून के मुताबिक केस डायरी मेंटेन नहीं रखने पर पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को इस मुद्दे पर गैर करने का निर्देश दिया है। न्यायपूर्ति ए पुलिस द्वारा आयोगी और न्यायपूर्ति श्याम चांडक की खंडपीठ ने 16 जनवरी के अपने आदेश में कहा कि उसे नियमित रूप से ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जहां कानून के अनुसार पुलिस द्वारा केस डायरी का रखरखाव नहीं किया जा रहा है।

**क्या है पूरा मामला ?**

पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर

### इस तरह के निर्देश जारी करने में हो रही परेशानी

अदालत ने कहा, 'ऐसा प्रतीत होता है कि डीजीपी द्वारा जारी निर्देश निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों तक नहीं पहुंचे हैं, जो जमीनी स्तर पर जांच कर रहे हैं और सर्कलर पुलिस स्टेशनों की फाइलों में ही रख रहे हैं।' पीठ ने कहा कि इस तरह जारी करने में परेशानी हो रही है, लेकिन नियमित रूप से ऐसे उल्लंघनों का सामना हो रहा है। पीठ ने कहा, 'हम उमीद करते हैं कि डीजीपी सभी पुलिस अधिकारियों से जाज्य में सर्वोच्च पुलिस प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में गंभीरता बढ़ते और ऐसे निर्देशों को हल्के में और या लापरवाही से न लें।' अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी की छव्वी के अनुसार पालन करने और उल्लंघन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा कि वह उमीद करता है कि डीजीपी कड़े उपचारात्मक उपाय अनुसारे पीठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा 'वह एक गंभीर विषय है। केस डायरी (वर्तमान में) न केल ढीली पड़ गई है, बल्कि ये पूरी तरह से विवरी चुकी है।'

## मराठा सर्वे से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित?



**मुंबई :** मराठा आरक्षण के लिए खुली ब्रेणी के नागरिकों का सर्वेक्षण आज, मंगलवार से होगा। अगले तीन दिनों तक सर्वेक्षण कार्य करेंगे। इससे तीन दिनों तक अस्पताल का कामकाज प्रभावित रहेगा। उसके बाद लगातार तीन दिनों की छुट्टियां हैं, यानी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की छुट्टी और उसके बाद चौथा सप्ताहांत। इसलिए अस्पताल प्रशासन को अस्पताल के कामकाज पर अतिरिक्त दबाव पड़ने का डर है।

**शिक्षा विभाग पर भी असर**

इस सर्वेक्षण में मुंबई नगर निगम के विभिन्न विभागों के छह हजार से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को भी करना होगा, इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर असर पड़ने का डर है। साथ ही शिक्षा क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है।

सर्वे 23 से 25 जनवरी तक चलेंगे और फिर लगातार तीन दिन छुट्टी है। इससे छह दिनों तक प्रशासनिक कामकाज का बोझ बढ़ने की आशंका है। नगर निगम के केईएम, नायर, शिव,

मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिन्टिंग प्रेस, गाला नं. 4, एन. के. इंडस्ट्रीयल इस्टेट, प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेट के अंदर, गेट नं. 2, गोरेंगवं (पूर्व), मुंबई- 400063 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेर्स्ट मुंबई : 4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : शॉप नंबर 4, मदीना मेंशन, C9 ए, कैडल रोड, अपोजिट बिल्लाबोंग

स्कूल, माहिम पश्चिम, मुंबई 400096, महाराष्ट्र मोबाइल नं 998777 5650 फ्रॉन्टस्प्प नं 7977408589: Email-editor@rokthoklekhaninews.com

नवी मुंबई में जौहरी से 1.9 करोड़ रुपये के सोने की ठगी

एक के खिलाफ मामला दर्ज



धारा 41ए के तहत किसको

दिया जाता है नोटिस

अदालत ने डीजीपी को अविकल रूप से मामले को देखने और संवर्धित पुलिस अधिकारी को खिलाफ अविकल कानूनी कानूनाई करावाई करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि वह यह जानकारी भी हैरान है कि सीआरपीसी की घारा 41ए के तहत नोटिस आरोपी अविकल (अधिकारीकार्ता की पती) को नहीं दिया गया और पंजाब में सह-अधिक्युट के एक रिसलेदार को दिया गया था। पीठ ने कहा कि घारा के अनुरूप नहीं है और घारा 41ए के तहत नोटिस केवल आरोपी को ही दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि हम जांच पुलिस अधिकारी द्वारा अनाएं गए नोटिस की सेवा के लिए विवाद करते हैं जो असमर्थ हैं। यह संवर्धित अधिकारी द्वारा घारा 41ए का स्पष्ट उल्लंघन है और इस पर पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी द्वारा अधिकारीकार्ता के पुलिस महानिदेशक को गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि वह अनुसारे पर लिये इस मामले पर 13 फरवरी को सुनवाई करेगा।

केस डायरी सीआरपीसी की घारा 172 (1-बी) की 'पूरी तरह से अवहेलना' में रखी गई थी। इसके महेनजर उच्च न्यायालय द्वारा कई आदेश पारित किए गए और महाराष्ट्र के डीजीपी द्वारा परिपत्र जारी किए गए, जिसमें जांच अधिकारियों को कानून के अनुसार सभी मामलों में केस डायरी बनाए रखने के निर्देश दिया गया।

डीजीपी को दिए निर्देश  
इसके बाद पीठ ने केस डायरी सहित पुलिस जांच दस्तावेजों का अवलोकन किया। पीठ ने कहा कि ताणे में गंभीरता से ध्यान देते हैं कि विवाद के अनुसार अधिकारी की छव्वी के अनुसार पालन करने और उल्लंघन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा कि वह उमीद करता है कि डीजीपी कड़े उपचारात्मक उपाय अनुसारे पीठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा 'वह एक गंभीर विषय है। केस डायरी (वर्तमान में) न केल ढीली पड़ गई है, बल्कि ये पूरी तरह से विवरी चुकी है।'

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

डीजीपी को दिए निर्देश  
इसके बाद पीठ ने केस डायरी सहित पुलिस जांच दस्तावेजों का अवलोकन किया। पीठ ने कहा कि ताणे में गंभीरता से ध्यान देते हैं कि विवाद के अनुसार अधिकारी की छव्वी के अनुसार पालन करने और उल्लंघन करने के निर्देश जारी किए गए हैं। अदालत ने कहा कि वह उमीद करता है कि डीजीपी कड़े उपचारात्मक उपाय अनुसारे पीठ ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा 'वह एक गंभीर विषय है। केस डायरी (वर्तमान में) न केल ढीली पड़ गई है, बल्कि ये पूरी तरह से विवरी चुकी है।'

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी की जाती है।

ताणे के निर्देश के तहत, पुलिस ने डीजीपी को नोटिस जारी कर बयान देने के लिए उपस्थित होने का निर्देश देना होता है और उसके बाद, अगर पुलिस उचित समझे, तो गिरफतारी क